भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 151
दिनांक 01 अगस्त, 2024

इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट

***151. श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नर्मदापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विचार है क्योंकि वहां गन्ना, धान, गेहूं और मूंग का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई कार्य-योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में, विशेषतः उक्त संसदीय क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए सरकार और पेट्रोलियम क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों द्वारा संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट" के संबंध में संसद सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती है। सरकार एथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अनेक उपाय कर रही है जिनमें एथेनॉल के उत्पादन हेतु फीड स्टॉक का विस्तार, ईबीपी कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत करना, देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और संवर्धन के लिए ब्याज इमदाद योजना आदि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण ईएसवाई 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2022-23 में 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है और मिश्रण प्रतिशतता में तदनरूपी वृद्धि हुई है तथा यह 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 12.06 प्रतिशत हो गया है। ओएमसीज ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य जून, 2022 अर्थात् एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2021-22 के दौरान लक्ष्य से पांच माह पहले ही हासिल कर लिया था। चालू ईएसवाई 2023-24 के दौरान, मिश्रण का प्रतिशत पहले ही 13 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2022 में यथा संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की समय-सीमा वर्ष 2030 से घटाकर ईएसवाई 2025-26 की गई है और एथेनॉल के उत्पादन के लिए एक से अधिक फीड स्टॉक की अनुमति दी गई है। एक अंतरमंत्रालयीय समिति द्वारा तैयार किए गए भारत में एथेनॉल के मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25 में अनुमान लगाया गया है कि ईएसवाई 2025-26 में 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी जिसके तहत पूरे देश में 1528 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता उपलब्ध है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत निर्धारित मिश्रण लक्ष्य हासिल करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) के साथ दीर्घकालिक ऑफटेक करारों (एलटीओएज) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, अपनी निवेश योजनाओं के अनुसार परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों/कंपनियों/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2018-22 के दौरान शीरा और साथ ही खाद्यान्नों से एथेनॉल के उत्पादन हेतु विभिन्न एथेनॉल ब्याज इमदाद योजनाएं (ईआईएसएस) शुरू की हैं।

नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में 5 एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ब्याज इमदाद को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	एथेनॉल परियोजनाओं का नाम
1.	नर्मदा शुगर्स प्रा.लिमिटेड
2.	शक्ति शुगर मिल प्रा. लिमिटेड
3.	वंशिका शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	नर्मदा शुगर प्रा. लिमिटेड
5.	के पी बायोफ्यूल्स प्रा. लिमिटेड

(ग) से (घ): किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता और फीड स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसीज) अर्थात आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और आईजीएल आगे विपणन हेतु सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चार सीबीजी संयंत्र चालू कर दिए गए हैं और दो संयंत्र निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में सीबीजी संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार अथवा पेट्रोलियम क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विचाराधीन नहीं है।

****